society was the dream of Thanthai Periyar of Tamil Nadu. I have got a dream of a country where there is no unemployment, where peace prevails everywhere, where people are one, where people are living together as Indians. I foresee that day, for which our services, our deliberations here, will help. I want to associate myself with that. I think I have to do a lot more in the days to come.

With these words, Madam, I once again thank you, I once again thank the President.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before I call the next speaker, the Secretary-General.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Bill, 1999.

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint six members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Bill, 1999 in the vacancies caused by the retirement of Sarvashri Janardhana Poojary, V. Kishore Chandra S. Deo, Dr. Ranbir Singh, Onkar Singh Lakhawat, Dr. Biplab Dasgupta, Gurudas Das Gupta, from Rajya Sabha and communicate to this House the names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha so appointed to the Joint Committee, may be communicated to this House."

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS - Contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Janeshwar Misra. After Misraji, it will be Shri Cho. Ramaswamy.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI) : The maiden speech should be followed by a tribute.

श्री जनेश्वर मिश्र : पहले बोल चुके हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is not a maiden speech. Misraji, you have to abide by the time- limit of 16 minutes. There are two speakers from your party.

SHRI RAM JETHMALANI: The earlier speech was a maiden speech to which he is supposed to pay a tribute. That is the tradition.

उपसभापति : 2 स्पीकर हैं आपकी पार्टी के और 16 मिनट हैं । जनेश्वर जी, आपकी पार्टी के 2 स्पीकर हैं और 16 मिनट का समय है ।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, इस धन्यवाद प्रस्ताव से एक बासीपन की बदबू आ रही है । महोदया, कई माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि यह प्रस्ताव बहुत पहले लाना चाहिए था । हमारे मित्र नायडू साहब यहां बैठे हैं । महोदया, इस सरकार की तरफ से पहले जो लोग धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते थे, उनको प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं टिका दिया । कोई गवर्नर बन गए, कोई मिनिस्टर बन गए । अब नायडू साहब दो बार से कोशिश कर रहे हैं । पता नहीं कब इनका नंबर आएगा ।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : आएगा, आएगा । बहुत जल्दी आएगा ।

श्री वेंकैया नायडू (कर्णाटक) : ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है मेरी। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, 5 साल, 10 साल में मैं पार्टी का ही काम कर सकता हूं ।

श्री जनेश्वर मिश्र : यह तो भंडारी जी भी कहते थे कि हमारी इच्छा नहीं है । यह तो कहा ही जाता है । ऐसा थोड़े ही है कि हम लोग इतनी भाषा नहीं समझते ।

महोदया, बासीपन की तरफ इशारा कई माननीय सदस्यों ने किया । गुजरात में एक सरकुलर जारी हुआ था जिसको लेकर यहां बहुत तनाव रहा । तनाव कई दिनों तक चला और आप लोग, हम लोग राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं कर सके । हालांकि उस सरकुलर का कुछ हुआ नहीं । वह जूता और प्याज वाली कहावत होकर रह गई लेकिन हम लोगों का समय तो जरूर खराब हुआ । तब से समय बहुत बदला है और कई घटनाएं हो गई हैं और अब मन नहीं करता कि राष्ट्रपति महोदय

ने पिछली बार जो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था, उस अभिभाषण पर जरा भी चर्चा की जाए ।

महोदया, हमारे राष्ट्रपति पिछले दिनों विदेश गए और उस देश के अखबार वालों ने छाप दिया कि ये "अछूत'' राष्ट्रपति हैं । महोदया, बासी चीज में अगर जहर मिल जाए तो उसे देखने तक का मन नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि विदेश के उस अखबार को सज़ा दे दी जाए या उसके ऐडीटर को जेल भेज दिया जाए।

[उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कम दुःखदाई बात नहीं है कि हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी, जिसके अभिभाषण पर हम लोग यहां चर्चा कर रहे हों, उन्हीं दिनों वे किसी दूसरे देश में जाएं और वहां के मीडिया वाले उनको "अछूत'' छाप दें । राष्ट्रपति महोदय की तरफ से इस बारे में जो बयान निकला है, वह भी मैंने पढ़ा है । वहां के अखबार के मालिक ने जो माफी मांगी है, वह भी मैंने पढ़ी है । राष्ट्रपति महोदय ने यह कहा है कि भारत के मीडिया के लोगों ने एक लंबे समय से हमारे बारे में इस तरह की खबर छापी है । इस मामले को अब खत्म समझ लिया जाए । और उन्होंने यह भी कह दिया कि हमारे दूतावास को जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, उसने ठीक से वह कार्यवाही नहीं की ।

महोदय, एक राष्ट्र का राष्ट्रपति विदेश में जाकर अपने देश के दूतावास के बारे में असंतोष व्यक्त करे, यह मामूली घटना नहीं हुई है । हम लोग किस पर चर्चा करेंगे ? भारत सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस बारे में मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता । यहां मंत्री लोग बैठे हुए हैं । भारत सरकार ने प्रतिक्रिया में क्या किया, इस पर बहस हो सकती है क्योंकि जिस तरह की जातीय व्यवस्था आज विद्यमान है और जो सवर्ण मानसिकता देश की राजनीति पर हावी है, उसमें बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठने पर भी जो दलित वर्ग का आदमी है, वह अपमानित ही होता रहेगा । अपने देश में भी अपमानित होता रहेगा और अपने देश के बाहर भी अपमानित होता रहेगा । यह भारतमाता का अपमान है । इस पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है । सरकार ने कुछ नहीं किया । इस पर ऐतराज़ करना चाहिए था । सख्त नोट देना चाहिए था। अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुला लेना चाहिए था । राजनीति करने के नाते ये सब बातें और इससे भी कड़ी बातें मैं बोल सकता हूं लेकिन हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है ।

महोदय, आज़ादी मिलने से पहले महात्मा गांधी ने जो सपना दिया था इस देश को, उस सपने में यह भी शामिल था कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो इस देश का पहला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत के हरिजन का बेटा या बेटी में से कोई होगा। उस

सपने को लेकर देश में दलित लोग सड़क पर निकल पड़े। ये दलितों के संगठन कुछ लोग जो चलाया करते हैं, मैं उम्मीद करता था कि फ्रांसीसी दूतावास तक यह लोग प्रदर्शक होंगे। लेकिन हम राजनीतिक कर्मी भी, लगता है कि हमेशा सतर्क नहीं रहते, हमारे दिमाग का कोई न कोई सेल कहीं न कहीं हमेशा सोया रहता है। हम बहुत पीड़ित है। इस अभिभाषण पर बहस करने का मन ही नहीं कर रहा है। जिस राष्ट्रपति को गौरव के साथ हम बग्गी पर बिठा करके, जुलूस बनाकर के सेंट्रल हॉल लाए, उन के भाषण को हमने सुना। सही है कि अब सरकार ने तैयार किया, राष्ट्रपति जी का अपना भाषण नहीं है। राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण थोड़ा सा अपने घर पर दावत में अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने दिया और खलबली मच गई थी कि यह तो स्वतंत्र तेवर दिखा रहा है, यह तो सरकार का लिखा हुआ भाषण नहीं था। लेकिन कहा जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय का है और सच कहूं उपसभाध्यक्ष जी, मैं शर्मिन्दा हूं इतनी दुर्गति से गुजरने के बाद हम भारत के लोग, यह संसद, यह सरकार देश की जातीय व्यवस्था के बारे में और उससे जो जहर और दुर्गन्ध आ रही है उसके बारे में सोचने के लिए कतई तैयार नहीं है। उसको भारत का अपमान नहीं मान पा रहे हैं। अगर इसी तरह की भाषा हिन्दुस्तान का कोई अखबार छाप देता कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो भारत में आया है उसके चरित्र पर कई तरह के लांछन लगे हुए हैं तो अमेरिका के लोग गरम हो जाते। लेकिन हमारा अखबार नहीं छापता। जिस तरह के किस्से कहानियों का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर क्लिंटन साहब आए, छः महीने, साल भर से यह प्रचारित था, अगर यहां का अखबार छाप देता तो बहुत बुरा हो जाता और वहां के लोग बवाल कर देते। लेकिन हम हरिजन के घर में पैदा हो जाएं हमको वहां के लोग अछूत कहदें और हम यहां जो कि अगड़ी जाति में पैदा हुए हैं हम उस पर ऐतराज नहीं करें क्योंकि हमारी सवर्ण मानसिकता का प्रतीक है और भारत अभी इससे मुक्त नहीं हुआ है। इससे मुक्त होने के लिए हमें गंभीरता से राजनीति और सामाजिक तौर पर चिंतन करना पड़ेगा। सबसे दुखी हो करके, मैं बहुत पीड़ित होकर के यह बात कह रहा हूं। यह बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा तो अभिभाषण इसलिए भी नहीं रह गया क्योंकि तब से पानी बहुत बह चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन साहब आए थे, जिस तरह से उनके आने पर उनका स्वागत किया गया है जबकि हमारे साथ कोई अजनबी आ जाता है तो एक मशीन लगा कर उसकी छानबीन की जाती है। मैं नहीं जानता कि अमेरिकी राष्ट्रपति के गुप्तचर विभाग के लोग जब उनकी सुरक्षा के लिए इस संसद की छत पर घूमने लगे होंगे तो उनकी भी उस मशीन से जांच हुई या नहीं हुई? इतना ही नहीं, एक अमेरिकी जांच एजेंसी है। लगता है कि हम गुलाम हो गए। 15 दिनों के अंदर होने लगे। उस जांच एजेंसी का दफ्तर भारत में खोलने की इजाजत

दी गई है। हमारे सी०बी०आई० के पूर्व निर्देशक जोगिन्दर सिंह ने कहा कि आई०एस०आई० और आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए यह दफ्तर बुलाया गया है। आपकी खुफिया एजेंसी को भी कोई बुलाता है? सरकार की तरफ से यह इजाजत दी जाती है। पाकिस्तानी गतिविधियों के लिए नजर रखने वाला आपकी गतिविधियों पर नजर नहीं रखेगा, उस समय आंखें मूंदकर रहेगा, यह यह कैसे मान लिया जाए? देश की स्वतंत्रता के मायने क्या हुआ करता है? यह इजाजत अभी-अभी दी गई है, गाजियाबाद के आसपास कहीं दफ्तर खुलने वाला है। लगता है कि हम गुलाम हो रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता नहीं रह गई है। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण जब तैयार किया गया होगा तब कहीं भी उनको भनक नहीं होगी कि यह सब होने वाला है। जिन दिनों यह अभिभाषण राष्ट्रपति पढ़ रहे थे उन दिनों मालूम नहीं होगा कि गुजरात में अकाल पड़ने वाला है, राजस्थान में पानी के बिना लोग तड़पने वाले हैं, जानवर भूख से मरने वाले हैं। आदमी बिना पानी के तड़पकर मर रहे हैं, गांव छोड़कर भाग रहे हैं। अब हम किस पर बहस करें, जो लिखा है उस पर या जो इस समय हो रहा है, उस पर। हमने पिछली बार भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ा था और बहुत ध्यान से पढ़ा था। उसमें एक लाइन थी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। बड़े दम्भ के साथ, श्री सोमपाल जी तो अब सदन में हैं नहीं, मिनिस्टर भी नहीं हैं, थोड़े बड़बोलेपन के आदि थे, बात-बार में वह बोलते थे कि दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन हिन्दुस्तान में होता है और उसके दो महीने के बाद मैंने देखा ...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : सर, इसे रिकार्ड से निकालवा दीजिए। बड़बोलेपन शब्द ठीक नहीं है। He can not defend himself. इसलिए उनके बारे में बड़बोलेपन ठीक नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी): नहीं, मिश्र जी आप कंटीन्यु करिए।...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव : यह प्रोवर्बियल बात है।

श्री जनेश्वर मिश्र : गौतम जी को तो टोकने की आदत है। वे हमारे मित्र है। ...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं तो आपके भाषण की प्रशंसा कर रहा हूं। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : अगर मित्र भी टोका-टोकी करें तो अच्छा नहीं है। लेकिन उन्हीं दिनों मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा था कि दूध जो पैदा करते हैं, गाय से दूध निकालते हैं, भैंस से दूध निकालते हैं वह सड़क पर आने को मजबूर हो गए। वे गोमती नदी में

अपना दूध बहा रहे थे क्योंकि उनको दूध बेचने की इजाजत नहीं थी, उनको मिलावट के नाम पर पीटा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था। गांव का गरीब ग्वाला एक तरफ गिरफ्तार हो रहा था। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश, अभी साल भर भी नहीं बीता कि दिल्ली में दूध का दाम बढ़ गया, जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं। वह दूध कहां गया? किस जगह पर चला गया? सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश तो हमारा देश है। मैं कल हिन्दू अखबार पढ़ रहा था। दुनिया में जितने टी.बी. के मरीज हैं उनमें से हिन्दुस्तान में अकेले 30 सैकड़ा मरीज हैं, दुनियाभर में जितने बच्चे अशिक्षित हैं, उनमें से 40 सैकड़ा हिन्दुस्तान के बच्चे अशिक्षित हैं, दुनियाभर में जितने बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं, उनमें से 45 प्रतिशत कुपोषण के शिकार भारतीय बच्चे हैं। यह खबर मैं अखबार में पढ़ रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है और ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार यहां के हैं। यहां के ग्वाले अपना दूध नदी में बहा रहे हैं और दिल्ली में दूध महंगा होता चला जा रहा है। एक साथ ये सब बातें हो रही हैं तो बड़बोलेपन को हमारे मित्र एतराज की भाषा मान सकते हैं। जो वस्तुस्थिति है उसको देखते हुए दूध कहां गया? वह पानी में बह गया, सबका चाकलेट बन गया, सबकी मिठाई बन गई, क्या हो गया? यह समझ में नहीं आया। एक बात मैं थोड़े से इशारे के तौर पर कह दूं कि कभी-कभी सरकार की तरफ से जो संयुक्त अधिवेशन के लिए अभिभाषण तैयार कराया जाता है उसमें बहकी-बहकी बातें कह दी जाती हैं। हमको अच्छी तरह से याद है। पिछली बार प्रधान मंत्री जी भाषण कर रहे थे, जब अभिभाषण का जबाव दे रहे थे तो इसी सदन में उन्होंने कहा था कि गराबों के लिए मैं सस्ते मकान बनवाऊंगा। आज भारत के एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री आन्दोलन कर रहे हैं कि गरीबों को मत उजाड़ो। उनको कहीं रहने की जगह दे दो। मैं कहूंगा कि यह गरीबों को मकान बनाने का वायदा बड़बोलापन है। मैं यह नहीं कहता कि शहर के गरीब ही गरीब हैं, गांवों में तो गरीबों की बहुत बुरी हालत है। जिसकी चर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा । देश की दौलत के बंटवारे में कहीं भी हम लोगों ने कानून के मुताबिक शक्ति नहीं दिखाई है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह बेचारा भरपेट खाने लायक तो बन जाए । हिन्दुस्तान की दौलत बंटने लगती है । यह बजट जो यशवंत जी ने पेश किया है इसमें सौ करोड़ में से दस करोड़ लोग मैं जानबूझकर बढ़ाकर कह रहा हूं आज उनकी जो आमदनी है, आने वाले कल में वह आमदनी बढ़ जाएगी । 15-20 करोड़ लोगों की जो आज आमदनी है, आने वाले कल में वह उतनी ही रहेगी और बाकी के 60-65 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आज जो आमदनी है, आने वाले कल में घट जाएगी और नीचे जाते-जाते कोई आमदनी नहीं रह जाएगी । यह हालत है । बजट का वह रूप ही नहीं बन पा रहा है कि कभी हम उनके बारे में भी सोचें । झुग्गी-झोपड़ी के

बारे में बोल दिया गया, नौजवानों के काम के बारे में बोल दिया गया, अपराधीकरण के बारे में बोल दिया गया। एक आयोग बैठा था श्रीकृष्ण आयोग । हमारे मित्र प्रधान जी बैठे हैं, वह बुरा मान जाएंगे । मुम्बई के दंगों की जांच करने के लिए यह आयोग बैठा था । जिन लोगों की पहले सरकार थी, उन लोगों ने उसकी रिपोर्ट कूड़ेदान में डाल दी। यह जज की जांच रिपोर्ट थी । एक नयी सरकार इन लोगों की बनी । हम लोग उम्मीद करते थे कि कार्यवाही होगी । सरकार थोड़ी-बहुत हिली, तब तक मुम्बई के नेता ने बोला कि अगर मेरे खिलाफ कार्यवाही हुई तो मुम्बई में और महाराष्ट्र में हमारे लोग आग लगा देंगे । कौन से अपराधीकरण पर रोक लगायी जा सकती है ? नहीं लग सकती है । यह भाषा सार्वजनिक रूप से बोली जाती है और वे लोग सरकार के मददगार लोग होते हैं । अगर इतनी अकड़ के साथ बोला जाएगा तो इस तरह से काम चल ही नहीं सकता है, हम एक कदम नहीं बढ़ सकते, साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बढ़ सकता है । जांच होती रहेगी, सरकारें बनती रहेगी, वह सरकारें कार्यवाही की धमकी भी देती रहेंगी लेकिन दूसरी तरफ से अगर कोई धमकी आ जाएगी आजकल हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। एक संस्था है जिसके बड़े-बड़े पदाधिकारी बोला करते हैं कि "न्यायालय जो भी फैसला करे, अयोध्या में मंदिर बनकर रहेगा ।" न्यायालय को हमारा फैसला मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । किसको डराने के लिए यह बोला जाता है ? अखबारों की कटिंग मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पढ़कर सुना दूंगा । यह भाषाएं डराने के लिए बोली जाएंगी और सौ करोड़ की जनसंख्या वाले देश को इकट्ठा करके रखा जाएगा, यह हो सकता है। कहीं न कहीं बैठकर बात करनी चाहिए कि अपनी भाषा पर काबू करो । देश को तोड़ने वाली भाषा बढ़ रही है। दूसरों पर आरोप मत लगाओ। यह सच है कि जो कमज़ोर होता है तादात में कमज़ोर हो, ताकत में कमज़ोर हो, जन्म से कमज़ोर हो, दौलत से कमज़ोर हो एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य होता है कि कमज़ोर की मदद की जाए। एक कल्याणकारी सियासत मानती है कि कमज़ोर की मदद करो। तादात में कमज़ोर अल्पसंख्यक हैं, जन्म से कमज़ोर पिछड़े और दलित हैं, दौलत से कमज़ोर किसान और मजदूर हैं - इस संसद में इस पर बहस होनी चाहिए थी कि इन कमजोरों की मदद की जाए - संविधान से ऊपर उठकर भी अगर मदद की जाए तो हमारे जैसे लोगों की समझ में आता है लेकिन बहस छेड़ी जाती है कि संविधान की समीक्षा कर दी जाए। यह एक निरर्थक बहस है । पढ़े-लिखे लोगों का दिमाग इसमें फंस जाता है । हम संसद में आने वाले लोग भी उसी में उलझ जाते हैं । लगता है कि यह सही है। मैंने एक बार और भी कहा था कि हिन्दुस्तान में कभी भी राजा नहीं बदला जाता था। एक बार पैदा हो गया तो वही राजा बना रह गया । अगर दूसरा आया, उसकी पलटन ने कब्जा कर लिया तो वह राजा बन गया नहीं तो राजा के

बाद उसका बेटा राजा बन गया। जनता को यह अधिकार नहीं था। 52 में भी अधिकार नहीं मिला था क्योंकि जनता को आदत थी कि जो कुर्सी पर बैठा है, उसी को बैठा दो। यह आदत बहुत दिनों तक चली। धीरे-धीरे हमारे नेता डाक्टर लोहिया, हमारे नेता श्री जय प्रकाश नारायण ने जनता को उकसाया कि जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उनको केवल बैठाना मत सीखो, उनको हटाना भी सीखो और लोगों की आदत कुर्सी से हटाने की पड़ गयी। पहली मर्तबा हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का गरीब आदमी....यहां पार्लियामेंट का मैम्बर नहीं, गरीब आदमी जब मैं कह रहा हूं तो खेत में हल चलाने वाला, सड़क पर झाड़ू देने वाला, अपने बच्चे के लिए स्कूल की फीस जमा नहीं करने की ताकत रखने वाला, अपने बूढ़े बाप की दवा नहीं जुटा पाने वाला यह महसूस करने लगा कि अगर हमारी उंगली में रोशनाई लग गई तो दिल्ली का तख्ता पलट दूंगा और यह दुख दूर हो जाएगा। यह बात 67 से, 77 से आ गई । अब चस्का लग गया तो कभी डेढ़ साल, दो साल बाद और एक बार तो तेरह महीने बाद ही बदल दिया । जो कोई कुर्सी पर बैठता है उसको यह मोह लगता है कि हम पांच साल क्यों न बैठें? हमेशा क्यों न बैठें? ज्यादा दिनों तक बैठने में भ्रष्टाचार के किस्से आने लगते हैं । जल्दी-जल्दी बदल जाने पर कम आते हैं। जितने लोग कम दिनों तक कुर्सी पर बैठे होंगे, उन पर आरोप नहीं लगे होंगे क्योंकि बेचारे समझ ही नहीं पाए, तब तक चले गए। जो लोग लंबे समय तक रह लेते हैं उन पर ज्यादा आरोप लगते हैं। दिल्ली से लेकर पटना, चेन्नई, मुम्बई तक जो लंबे समय तक कुर्सी पर रहे, उनके संबंध में कोई न कोई किस्से गढ़े जाते रहे हैं लेकिन लखनऊ में कोई लंबे समय तक नहीं रहा। पंत के ज़माने से आज तक मैं जानता हूं, जो कोई मुख्य मंत्री रहा, उसकी पांच साल की मियाद पूरी नहीं हुई क्योंकि दिल्ली वाले डरते हैं कि अगर पांच साल वह वहां बैठ गया तो दिल्ली पर वह कब्ज़ा कर लेगा। थोड़ी राजनैतिक सोच है यह लेकिन जहां कोई लंबे समय तक रहता है, कोई जेल जाता है, किसी पर मुकदमा चल रहा है, किसी के बारे में अखबार में छप रहा है, सब कुछ होता रहता है। इस गरीब और अशिक्षित देश में अगर कोई लंबे समय तक कुर्सी पर बैठा रह गया तो वह तानाशाह बनेगा, वह भ्रष्ट बनेगा लेकिन अब इच्छा हो गई कि पांच साल से पहले चुनाव न हों चाहे बहुमत हो या न हो। चुनाव के समय ही कहा गया कि संविधान की इस धारा को हम बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? अगर हिंदुस्तान का गरीब आदमी दो साल में अपनी हुकूमत बदलना चाहता है, उसके बच्चे को दूध नहीं मिलता, उसके बाप को दवा नहीं मिलती, उसके खेत को पानी नहीं मिलता, वह आपको कुर्सी पर नहीं रहने देना चाहता क्योंकि आप तो कह कर गए थे कि ये सब दूंगे तो आप क्यों पांच साल तक भोगेंगे ? ये सब मुद्दे हैं जिन पर बहस चल रही है। फिर समाज में जो कमज़ोर हैं, उनको डर लगता है कि ये हमारी मस्ज़िद पर

कब्ज़ा कर लेंगे, हमारे कब्रिस्तान ले लेंगे, हमारी शरीअत पर धावा बोल देंगे और इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस सरकार के लोगों से कहूंगा कि यह समीक्षा न कराएं। इसके दुष्परिणाम हो रहे हैं। आशंकाएं एक तरफ और आपके ऊपर उंगली उठ रही है कि लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने के लिए आप कोई साज़िश कर रहे हैं। यह हो तो सकता नहीं क्योंकि दोनों सदनों में आपका बहुमत नहीं है लेकिन कहीं-कहीं सुनने को मिलता है नायडू साहब संविधान समीक्षा का सारा एजेंडा पढ़ रहे थे - ये काम कर दूं, आप इसका विरोध करेंगे, ये काम कर दूं, आप इसका विरोध करेंगे - तो हमको हंसी आ रही थी कि पता नहीं समीक्षक कौन हैं और धन्यवाद प्रस्ताव में ये सारा एजेंडा डिक्लेयर करते चले जा रहे हैं।

महोदय, धारा 356 के बारे में कहा गया है कि इसको हटा दिया जाएगा। सरहद पर, देश के किनारे जो सूबे पड़े हैं क्या खतरा नहीं है कि अगर उनके ऊपर उचित ध्यान नहीं दिया गया, जिस तरह की क्षेत्रीय विषमताएं हैं, वे कह दें कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे? तो यह तो देश को जोड़ने वाली धारा है । हम लोग भी कभी-कभी जब इसका दुरुपयोग होता था तो इसका विरोध करते थे । हमारी सरकारें बरखास्त हुई हैं कांग्रेस के ज़माने में । हम लोगों ने इसे नहीं चाहा लेकिन यह देश क्या ऐसा बना हुआ है कि कोई भी सूबा कभी भड़क कर हमको छोड़ कर चला जाए और हम चुपचाप उसको बरदाश्त कर लें? यह नहीं हो सकता है । बढ़िया-बढ़िया बातें कह कर फुसलाओ मत देश को । लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने के लालच में संविधान को बदलने की नीयत रखकर देश को फुसलाओ मत और हर बात पर कहना कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने संविधान बदलने की साज़िश की, इन लोगों ने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा जी ने जेल भेजा, ठीक है उन्होंने भेजा। हमने उसका विरोध किया था । हम भी जेल गए थे। क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि आपके ज़माने में भी हम लोग जेल जाएं और हमारे साथ ये लोग जेल जाएं? उन दिनों आप हमारे साथ जेल गए थे । थोड़ा तो हम लोगों पर रहम कर दो। हमने उस समय भी विरोध किया था।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी) : मिश्र जी, आपको वाइंड अप करना पड़ेगा।

श्री जनेश्वर मिश्र : हां, बस दो मिनट और लूंगा। मैं नहीं जानता आप जाएंगे या नहीं लेकिन आपको उन लोगों का साथ छोड़कर हमारे साथ आना पड़ेगा, यह मैं जानता हूं। क्योंकि जो कोई भी अधिनायकवादी प्रवृत्ति का हो जाता है- अब हम लोग गुजरात पर बहस नहीं कर सकते, महंगाई पर बहस नहीं कर सकते, देशभर में पुलिस का जुल्म हो रहा है, उस पर बहस नहीं कर सकते। हमारे दिमाग और देश के दिमाग को संविधान समीक्षा के बारे में पलट सा दिया गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि जैसे गुजरात वाले

सर्कुलर पर प्रधान मंत्री जी की तरफ से फाइल बन्द हो गई थी, इस समीक्षा वाली बहस को भी प्रधान मंत्री जी की तरफ से हमेशा-हमेशा के लिए फाइल बन्द कर दी जाए ताकि देश लोगों के दुख-दर्द के बारे मे बहस कर सकें। पानी बिना जानवर मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। यह केवल गुजरात, राजस्थान और आन्ध्रप्रदेश में नहीं है बल्कि मध्यप्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, हमारे लोहगरा बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के लोहगरा और शंकर गढ़ के इलाकों में लोग जानवर लेकर भाग रहे हैं। पानी बिना जानवर तड़प रहे हैं, आदमी तड़प रहे हैं। पानी का इंतजाम नहीं है, इस पर बहस होनी चाहिए। एक तरफ तो प्रधान मंत्री जी देश के नाम संदेश देते हैं कि "मुक्त हाथ से दान दो, लोग पीड़ित हैं'। हम लोगों को समझ में नहीं आता कि खजाना कहां गया? सरकार भीख पर नहीं चला करती है। बड़ी से बड़ी आफत में सरकारी खजाने से, बड़ी से बड़ी योजनाओं की कटौती करके पूरी करनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी हमारी बिरादरी के हैं, हम लोगों की आदत है पंण्डित जी, हम आमतौर से झोली फैला दिया करते हैं, यह हम लोगों की आदत है, यह हम लोगों का धन है। उन्होंने कहा तो हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन देश तकलीफ में है। हम चाहेंगे इस तकलीफ के निवारण के लिए एक संजीदा बहस होनी चाहिए। इस फिजूल की बहस पर हम लोग अपने दिमाग को बिगाड़ रहे हैं, इससे मुक्त होना चाहिए। हमारे नेता रमा शंकर कौशिक जी हैं, जब हम इस अभिभाषण पर बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए दो-चार मिनट छोड़ देना। वे हमारे नेता हैं इसलिए मैं आपका शेष समय उनके लिए छोड़ते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI CHO S. RAMASWAMY (Nominated): Sir, the hon. President has expressed confidence that there is a distinct upturn in the economic situation and that efforts are on to bring the fruits of reform to those sections which had been ignored. But there are many voices of protest even in the ruling alliance. There is dissidence on liberalisation, privatisation and globalisation. And I do not know what is going to happen. If not now, at least, later on, this Government and the successive Governments would be forced to change track, and, in my opinion, it will be a tragedy because we are not giving anything a fair trial. We tried socialism. We abandoned it in the middle. Now, we are trying market economy. But because of protests, because of voices of dissent, I do not know what is going to happen to it. I am reminded of a popular story. A man was given a punishment by a local panchayat. He was given three options - take 100 chillies or take 100 onions or surrender all his money, all his savings, and go back as a pauper. This man agreed to take 100 chillies, and he started taking them. But, by about 80 chillies, he found it very difficult; his stomach started burning; his eyes

started watering. So, he said, "No, I will not take this chilli treatment, but I will take the onion treatment." Then, he started with the onions. But, half way through, he found it difficult; his stomach started crying for help. So, he said, "I don't want this onion treatment either. I will surrender all my money and go back as a pauper." Likewise, we took the chilli treatment first - socialism. We found it hard. We found it impossible. So, we abandoned it in the middle. Then, we started taking the onion treatment, that is, market economy. Let us continue with it. Let us not go back totally ruined, by giving it up in the middle. But, at the same time, care has to be taken to see to it that the less-privileged are taken proper care of. Food subsidy is an item which, in my opinion, has to be retained. In the United States, there is health care. In our country, I consider food subsidy as a health care because it supplies the basic need for the poor of this country. They are being asked to make sacrifices by taking rice supplied through the PDS. They are making a sacrifice already because the quality of rice is so bad. So, asking them to make a double sacrifice and pay a higher price is not fair. We would require the cooperation of all the people, particularly, the less privileged people, in order to make liberalisation a success. Therefore, I feel that we could call it our health care programme. That way, perhaps, we would be able to convince even the international institutions.

On Constitution review, it was suggested that persons who were prepared to cut off limbs are now objecting to obtaining a medical report. I agree with the idea. It is illogical to say, "conduct any number of operations; let there be any number of surgeries, but don't have an overall medical report before you do anything." I find this illogical. At the same time, I have my own reservations whether it is the right time for a review of the Constitution. When the Constitution was drafted, the country was experiencing a great pride in the newly acquired sovereignty. There was unity amongst all sections of the people, all varieties of people, all shades of opinion. Divisive forces had gone to the corner. They were totally ignored. And the leaders were such that they inspired confidence in every single Indian. But, now, the situation is totally different. When we are going to review the Constitution made during those times, the time must be as conducive as that for a review. Now there are divisive forces. What will be the demands that would come forth? The demands will be based on regional chauvinism, on language fanaticism, on casteism. There will be demands for dilution of the independence of the judiciary. There will be demands with an eye on the

communal vote. To avoid all these things, I think, it will be better not to indulge in this exercise now. But nothing is going to happen because of the appointment of the Commission. There will be no great danger to the Constitution. No amendment is going to be made by the Commission. After all, it is the Parliament which has to amend the Constitution. No doubt, the Commission consists of eminent persons - persons of unimpeachable character, integrity, intelligence and experience. So, one need not be afraid of the work of the Commission. But the main objection is whether the time is conducive for this exercise.

Sir, coming to the third point, the President has expressed his confidence that by the year 2001, all children between the ages of 6 and 14 in this country would be going to schools. As I said in a different context, this is the triumph of hope over experience. Let us think why our people, the rural folk, the under-privileged, the poverty-stricken people of this country, are refusing to send their children to schools. It is because they cannot afford to feed a mouth which is not productive. A child must become productive even at the age of five or six if the family is to survive.

That is why they are not sending their children to school. We should take an entirely different attitude towards education of the lesser-privileged classes. We should first ask ourselves; are these children living in such conditions which are conducive for learning, for getting educated and so on? You have slums, ill-provided villages, families which gamble, familes which indulge in illicit distillation. This is the atmosphere in which these children live. How can they learn in this atmosphere and achieve parity with the other classes of people? So, in my opinion, these children must be given the best of education and, that too, in residential schools. All over the country, on a war-footing, residential schools must be started for the poorest of the poor. Well, it would entail expenditure. But one could attack the other spheres -- intensify disinvestment, intensify the efforts to reduce the strength of bureaucracy. But whatever money is spent on this programme would be well-spent. It is as important as spending money on defence. The parents could be asked to visit the children once in a fortnight or once in a month. They would be provided with a few sets of uniform; a thatched shed with an asbestos' roofing would do. By providing residential accommodation and food and education, definitely, I think, in about 15 years, the entire scenario of the country would have undergone a remarkable change.

I am disappointed, Sir, that the President has not referred to the problems being faced in sharing of the waters between different States. Tamil Nadu, for example, is still to reach an agreement with Karnataka on Kavery. The Prime Minister, recently, a couple of days back, has referred to drought in two States and he has asked the entire nation to help. He is very right. But should a State be affected by drought before other States are prepared to cooperate with it? For twenty years, Kavery talks have been going on. For several years now, the State Government has been saying that it will be receiving the Krishna waters for the drinking purposes of Madras city. Lord Krishna may come, but we do not know whether the Krishna water will come or not! That seems to be the situation. What is the role of the national parties? The national parties in both the States take different stances in the States. In Karnataka, they say, "No Tribunal. No Water". In Tamil Nadu, they say, "Obey the Tribunal's order; give water to Tamil Nadu". Is this not hypocritical on the part of the national parties? On the part of the regional parties, I am able to understand this. I could understand a regional party in Tamil Nadu taking one view and a regional party in Karnataka taking another view. But both the main national parties, the BJP and the Congress, are guilty of this. They take one view in Karnataka and another view in Tamil Nadu. I don't know how they become national by taking two different views, to suit their regional purposes, to vie with the regional parties there. There must be a solution to the water-sharing problem. A State need not be affected by drought before other States are willing to cooperate with it.

Finally, I personally feel that the President's Address is a ceremony; the Parliament's Motion of Thanks is a formality, and the Members support is a gesture. I make this gesture. I support the Motion. Thank you.

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 23 फरवरी को राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये अभिभाषण पर माननीय वेंकैया नायडु द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संविधान की समीक्षा का भी जिक्र किया है और यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने उसके बारे में पक्ष में और विपक्ष में अनेक प्रकार के तर्क दिए और शंकाएं जाहिर की हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की शंकाएं निराधार हैं। हम एक साथ विचार करें कि देश में इन 50 वर्षों में हमारे समाज की जो उपलब्धियां होनी चाहिए थीं या हमारे समाज का जिस तरह से विकास होना चाहिए था क्या वह विकास हुआ है। हमारी जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है। हमारे समाज में गरीबी तीव्रता से बढ़ी है। हमारे समाज में क्षेत्रीय असंतुलन

तीव्रता से बढ़ा है। हमारा प्रशासन तेजी से पंगु हुआ है। हमारे प्रशासन में भाई-भतीजावाद बढ़ा है। हमारे राजनीतिज्ञों की सोच छोटी हुई है। इन सबके बारे में विचार करना आवश्यक है। क्या यह हमारे व्यवहार के कारण हुआ है या संविधान के बारे में ही हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिनका यह कहना रहता है कि वर्तमान संविधान में, जो ब्रिटिश इंडिया रूल था उसकी बहुत सी बातों को उसमें उल्था जस का तस कर दिया गया है और इसके कारण जो उसमें शक्ति आनी चाहिए थी, जो सामर्थ्य आनी चाहिए थी उसकी कमी हो गयी है। राष्ट्रपति जी ने देश के लोगों को आश्वस्त भी किया है, उन्होंने कहा है कि संविधान के मूल ढांचे और उसकी प्रमुख विशेषताओं को अक्षुण्ण रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पिछले 50 वर्षों के अनुभवों की जांच की जाए जिससे कि संविधान में प्रतिस्थापित उन आदर्शों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके। इसलिए सरकार ने एक व्यापक आधार वाले संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया है। इस आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जाएंगी जो भारतीय लोकतंत्र में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसलिए जैसे जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि वे कर तो नहीं सकते हैं लेकिन लोगों में शंकाएं हैं। जब कर नहीं सकते हैं तो फिर शंकाओं का कोई आधार नहीं है। इसलिए मित्रों किसी भी प्रकार से, भिन्न प्रकार से हम कहते हैं लेकिन हम कठिनाइयों को जानते हैं और उन कठिनाइयों का समाधान होना चाहिए। यह सबके मन में रहता है।

आज गांव की बात भी यहां बहुत लोगों ने की और मैं भी गांव की बात करना चाहता हूं। गांधी जी भी गांव की बात करते थे और गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव का देश है। लेकिन भारत में गांव की स्थिति कैसी है? गांव में दो प्रकार के लोग हैं - एक सम्पन्न लोग और एक विपन्न लोग। सम्पन्न लोग भय के कारण गांव छोड़ रहे हैं और विपन्न लोग साधनहीनता के कारण गांव छोड़ रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि आपके जो बड़े शहर हैं वे नर्क होते जा रहे हैं। गांवों में तो फिर भी एक प्रकार का मिला जुला भाव था, एक प्रकार की आत्मीयता है लेकिन शहर में केवल आवश्यकता होती है। इस प्रकार से शहर एक प्रकार के शोषण के केंद्र बनते जा रहे हैं। एक प्रकार के अभाव के केंद्र बनते जा रहे हैं और यह चिंता का विषय है। जब हम इस गांव के गरीब की बात करते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा चिंतन है एक बार आप उस पर विचार तो करिए। अपना देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए जल चाहिए। जल के लिए विद्युत चाहिए। लेकिन हमने रास्ता कौन सा अपनाया है? हमने रास्ता अपनाया है गैस की बिजली का, हमने रास्ता अपनाया है कोयले की बिजली का। मैं पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला हूं और मेरे यहां आज भी लगभग 1200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है जिसका मूल्य 18 से 20 पैसे प्रति यूनिट है। हम

18-20 पैसे प्रति यूनिट की जो बिजली है वह अपने किसान को, अपने गरीब को उसकी खेती के लिए उसकी सिंचाई के लिए जैसे आज की सरकारें वोट के लिए करती हैं, कि हम फ्री बिजली देंगे। इस देश में फ्री बिजली देना संभव नहीं है। अगर हमारी बिजली 18 से 20 पैसे है तो हम 50 पैसे में दे सकते हैं, हम एक रुपए में दे सकते हैं। अगर हम दाभोल में एनरान से साढ़े 4 या 5 रुपए में बिजली पैदा करवाएंगे या बाकी कोयले से निकलने वाली बिजली को 4 या 5 रुपए में पैदा करेंगे तो फिर हम उसको नहीं दे सकते हैं। अगर हम रुपए में देते हैं तो जैसे हमारे सामने उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, विद्युत परिषद की स्थिति है वह इसी तरह आएगी। इसलिए आज हमको पूरे के पूरे कार्यकरण पर विचार करना पड़ेगा। यह पूरा का पूरा कार्यकरण क्या रहा है? मैंने मनमोहन सिंह जी का भाषण सुना है। वे बहुत बड़े नेता हैं । विपक्ष के भी नेता हैं। बहुत बड़े पद पर रहे हुए भी हैं। वह समाज के बारे में चिंता कर रहे थे कि साहब, अगर धर्मनिरपेक्षता होगी तो यह हो जाएगा, और नहीं होगा तो यह समाज टूट जाएगा । मैं उनके पूर्वजों की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । कांग्रेस इस देश की बड़ी पुरानी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस ने केवल सत्ता के आदान-प्रदान के अलावा क्या कभी मूल्यों का भी निर्वाह किया है? कांग्रेस ने विफलता के बाद, जब कांग्रेस इसके प्रयास में थी कि आजादी की लड़ाई के बाद यह देश न टूटे और उसी समय देश टूट गया तो कांग्रेस ने धर्म-निरपेक्षता के नारे को पकड़ा । अब यह 'धर्म निरपेक्षता' तो कहा गया शब्द है, अच्छा शब्द तो 'पंथ निरपेक्षता' है । अच्छा शब्द तो सर्व धर्म समभाव है । भारत के लोग धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकते हैं । 1971 में समाजवाद की गूंज आसमान पर थी। मैं उन महापुरुषों का नाम नहीं लेना चाहता, वे अच्छे लोग थे, लेकिन उस समय गूंज थी। बाद में उसे कांग्रेस की सरकारों ने छोड़ दिया। उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। इस तरह से हम केवल शब्दों के आधार पर राजनीतिक आवश्यकता के लिए जो आचरण करते हैं उसके कारण ये सब हमारी पीड़ाएं हैं। कांग्रेस विफल हुई थी। अभी समाचार पत्रों में गाडगिल जी की एक श्रृंखला छपी थी। गाडगिल जी आपके बड़े नेता हैं । बुजुर्ग हैं। कुछ दिन पहले वह यहां बैठते थे। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को धर्म निरपेक्षता का रास्ता छोड़ देना चाहिए । क्या वे कांग्रेसी नहीं हैं? वे कांग्रेसी हैं और आपसे अच्छे कांग्रेसी हैं। लेकिन इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस ने यह नारा तब दिया था जब इस देश में द्विराष्ट्र के सिद्धांत की बात हो रही थी। जब इस देश में मुस्लिम लीग अलग राज्य की बात कर रही थी और अलग राष्ट्र बन गया । फिर भी आपने संशोधन नहीं किया अपनी उस नीति में। इस देश में जब तक हिन्दू समाज है तब तक यह प्रजातंत्र रहने वाला है, क्योंकि हिन्दू समाज मूल रूप से प्रजातांत्रिक है । मुंडे मुंडे मतै भिन्ना। हमने पंथों के आधार पर राजनीति और राष्ट्र

का विचार नहीं किया है, हमने संपूर्णता का विचार किया है। इसलिए मैं कांग्रेसी मित्रों से कहता हूं कि आज अवसर आ गया है कि वे अपनी कथनी और करनी में अंतर करें और अपने राष्ट्रीय दायित्व को समझें । आज भी कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज क्षेत्रवाद बढ़ रहा है। मैं भी एक किनारे के क्षेत्र का हूं। आज क्षेत्रवाद बढ़ रहा है । इसमें किसकी विफलता है? सत्ता के शीर्ष पर चलने वाली जो नहर थी उस नहर का पानी वहां तक पहुंचा नहीं। लोगों की चिंता नहीं हुई, आसाम की चिंता नहीं हुई, मणिपुर की चिंता नहीं हुई, नागालैंड की चिंता नहीं हुई, और मेरे पहाड़ की भी चिंता नहीं हुई । इसके लिए कौन जिम्मेवार था? अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार था तो वह कांग्रेस थी । मैं अपने डीएमके के किसी सदस्य का भाषण सुन रहा था । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 356 की धारा नहीं रहनी चाहिए । यह शंका क्यों पैदा हुई, क्योंकि हमने ऐसा आचरण किया है। हमने वहां की सरकारें तोड़ी हैं । इस सारे परिप्रेक्ष्य में आज जहां संविधान समीक्षा व सुधार की आवश्यकता है और पूरे देश के लोगों को इस राष्ट्र की सम्पत्ति में, इस राष्ट्र के राजस्व में, इस राष्ट्र की प्राप्तियों में उनको कैसे स्थान मिले, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है, वही राजनीतिक दलों को अपनी कथनी और करनी के आचरण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । आज हम यहां केवल कहने के लिए कहते हैं, हम उसको करते नहीं हैं । यहां जो कुछ भी कहते हैं केवल कहने के लिए ताकि अमुक बात रेकार्ड में आ जाए, मित्रों यह 50 वर्ष से रेकार्ड में आने वाली बात हो गई है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी० एन० चतुर्वेदी) : ध्यानी जी, आपका टाइम समाप्त हो रहा है ।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी : अच्छा, समाप्त करते हैं । आखिरी बात कहता हूं । आज स्थिति यह है कि सब लोगों को इस प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए और इस देश के श्रेष्ठ मूल्यों को जीवित रखने के लिए और मानव और संसार को कुछ देने के लिए सब लोगों को अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए और इसी परिप्रेक्ष्य में जो भी संविधान में उचित संशोधन करने योग्य है, वह संशोधन करके सारे समाज को उसके लाभों को देने की स्थिति पैदा करनी चाहिए ।

मैं अपनी अंतिम बात पर आता हूं। राष्ट्रपति जी ने उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की बात कही है। ये मुद्दे कुछ नए नहीं हैं। मैं जब पहली बार इस राज्य सभा में आया था तो मैंने पंडित नेहरू जी के नाम का उल्लेख किया था और मैं आज भी करना चाहता हूं। नेहरू जी ने 1937 में श्रीनगर की सभा में 5 मई को कहा था.....।

महोदय, नेहरू जी से लेकर नरसिंह राव तक एक लंबा समय गुजर गया है, लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्र कभी साफ बात नहीं करते हैं। वहां तो आंदोलन करते हैं, लेकिन यहां कोई बात नहीं कहते हैं। महोदय, मुद्दा चाहे ऊधमसिंह नगर का हो या हरिद्वार का हो - ये दोनों उस के अभिन्न भाग हैं और उस में रहने चाहिए, लेकिन कांग्रेसी मित्रों ने कभी साफ बात नहीं कही। महोदय, जनता दल की सरकार के समय उन्होंने भी यह बात कही थी कि हम यह राज्य बनाएंगे और हम ने कहा था कि अगर जनता दल प्रस्ताव लाएगा तो हम उस का पूरा समर्थन करेंगे। परंतु मेरे कांग्रेसी मित्रों को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि केवल राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक बात कहना, जैसी कि उन्होंने पंजाब विधान सभा में इस बारे में कही, ठीक नहीं है ।

महोदय, हमारे यहां प्रदेश हैं, लेकिन हम देश को संघों का राज्य कहते हैं । एक राज्य दूसरे राज्य के बारे में बात कहता है । आप के ही एक सदस्य ने, मैं उन का नाम लेना ठीक नहीं समझता, उन्होंने दूसरे लोगों को वहां की बात कहने के लिए प्रोवोक किया उनके थोड़े से लोग ऊधम सिंह नगर में रहते होंगे, लेकिन उस से कोई फर्क नहीं पड़ता । महोदय, हमारे लोग भी अमृतसर में 20 लाख में से 4-5 लाख हो सकते हैं और कोई आदमी कहीं रहता है, इस का कोई अर्थ नहीं होता । कांग्रेस इस इरादे से कि हम राज्य सभा में कोई भी बिल पास नहीं कर सकते और लोक सभा में भी हमें उन की आवश्यकता होगी ऐसा विचार न करते हुए, कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपनी बात साफ करनी चाहिए और न केवल लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति बल्कि नेहरू जी जो बात कहते रहे, नरसिंह राव जी जो बात कहते रहे - उन की आकांक्षाओं की भी पूर्ति करने के लिए इस विधेयक का समर्थन इस रूप में करने की घोषणा करनी चाहिए ।

इसी के साथ आप का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI VAYALAR RAVI : Sir, the President's Address is a policy statement of the Vajpayee Government. I am unable to appreciate or agree with certain formulations in the Rashtrapati's Address. We speak of a Constitutional review. Our leader, Shri Pranab Mukherjee, elaborately dealt with that question. I do not want to go into that. The President's Address says, "...it has, however, become necessary to examine the experience of the past fifty years to better achieve the ideals enshrined in the Constitution." Yes. What are the great values? Our Constitution is Sovereign, Socialist, Secular and Democratic. That is what the Preamble of the Constitution says. Now, we are hearing about the attacks on the secular credentials of this country from the hon. Members on the other side. Before coming to the

point, I appreciate my friend, Mr. Siva's speech. It was his maiden speech. The speech itself shows the greatness of the Constitution because he belongs to a particular political party which, once upon a time, demanded a separate Dravidian State. But they had to give up that demand. The demand was, "We want a separate Dravidian State. We are not a part of India." This was the slogan of that political party once upon a time. But they changed this because they understood the greatness of the Constitution...*(Interruptions)*...I am only making a statement of fact...*(Interruptions)*...That is what I am saying...*(Interruptions)*...You have given it up because of the greatness of the Constitution. That is what I am saying. I am saying that you have understood the greatness of the Constitution and given up your demand. I am appreciating that. When you are quoting the past and the statements of the main leaders, do not forget what had happened in the past. Sir, today, what is happening to secularism? Secularism is under attack. It is under attack even in this Parliament. It is under attack, and you know who is leading that attack. That is the main question. It is no less than the Home Minister, Mr. L.K. Advani. He wrote a series of articles, calling it pseudo-secularism. And hon. Mr. B.P. Singhal, who is speaking on behalf of the BJP, also called it as 'pseudo-secularism.' Mr. Advani not only continued his attack on the secular credentials of this country, but also put it into practice, when he himself witnessed the demolition of Babri Mazjid. That is why he became an accused in that case. But, of course, it is a political morality; it is left to him whether to continue in this Government. It is up to him. I am not demanding that. Sir, coming to the other points in the Constitution, Mr. Pranab Mukherjee, has asked a specific question, because they are making an allegation that the Congress had done it. Yes. The Congress amended the Constitution. Yes. Pandit Jawaharlal Nehru himself was given the leadership and he amended the Constitution for the first time. Why? And, later the then Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, during the seventies, amended the Constitution. I was a Member of the Lok Sabha at that time.

There was an explanation, given by Shri Pranab Mukherjee, as to why it had been done. During the Constituent Assembly also, Shri Jawaharlal Nehru said, "Yes, we may have to change at times." But nobody -- at any point of time - said that they want a new Constitution. Why does the BJP want to have a new Constitution? The Constitution of other nations is the product of a revolution, while this Constitution is the production of our

Freedom Movement. I am sorry, Mr. Venkaiah Naidu, you have nothing to claim by way of contribution to the Freedom Movement. So, why do you want to change it? ...*(Interruptions)*... Okay, your party has contribution. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Mr. Vayalar Ravi, you have only 18 minutes.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am not interrupting him. I have regard for him. But, we never said that we want a new Constitution. Let it be on record. *(Interruptions)*

SHRI VAYALAR RAVI: Now, the other point is, the Indian Constitution is very much associated with the name of Dr. Ambedkar. You can definitely change the new Constitution. I am afraid, is it an allergy towards something or towards some people belonging to certain sections of this country? I do not know. That you have to explain. Then, at page 2, they say, "As experience of many newly developing nations has shown, fifty years is a long time to achieve order and progress." Sir, this period of 50 years has been a period of coalition Governments in this country. Our Constitution provides for coalition in the States and at the Centre. Many political parties came to power. So, nobody can point a finger at each other and blame each other. In 1957, a non-Congress Government came to power in Kerala; in 1967, this country witnessed defection of Governments in the States like UP, Madhya Pradesh, Haryana. In 1977, a non-Congress Government came to power in Delhi and that was the beginning of the retardation of the progress of the nation. They had given up the process of planned economy and they started the rolling Plan. The whole body politic became fragmented. From 1977 onwards, the progress of the country went back by 25 years. You people are responsible for that retardation, not we. You look at the whole situation today. Look at the political situation today; they come up with the NDA, BJP being the major party and other parties as partners. When you attack the Constitution and secularism, you continue to attack the minorities in different States. I do not want to go into the details because this matter has already been discussed here. But I would like to know from you, Mr. Venkaiah Naidu, whether you party and your Government would uphold the principle of the Constitution and the right to freedom of religion in this country. Unfortunately, in UP, in Gujarat and in other States, where your party is in power, the attacks on minorities are continuing, and it has

continuously been suffocating the freedom of religion in this country. That is one of the dangers to the unity of this country. So, I demand that this issue should be discussed in the National Integration Council, which is the proper forum for a discussion of this kind of issues. I wish this Government and Mr. Vajpayee, the Prime Minister, take the initiative to discuss this issue and call a meeting of the National Integration Council because this is one of the appropriate fora where we can discuss such issues.

Sir, now I come to the constitutional amendment with which the judiciary is concerned. The First Citizen of India made a speech at the Golden Jubilee celebrations of the Supreme Court. Judiciary has no power to amend the Constitution. Article 124 and 125 deal with the appointment of judges. The judiciary itself entered into the field of the right of Parliament to amend the Constitution by giving a judgement as to how judges should be appointed, which I don't approve. At the same time, the judiciary is said to have reflected certain sentiments. In this connection, Sir, I quote from the speech made at the Golden Jubilee celebrations of the Supreme Court. It says, "In our vast country, with its immensity of diversities, it is a matter of importance that in judiciary, all major religions and sections of the society are represented, to the extent possible, consistent with the requirement of merit and the high standard maintained by our judiciary....."

" The argument is not that the judiciary should follow some sort of proportional representation that administration of law and justice is intimately inter-linked with the social philosophy of the judiciary, and the social philosophy cannot be entirely separate from the social origins of those who dispense the justice".

Sir, this is one of the major landmarks of the speech of the first citizen because by this he has conveyed a message. But what has your Government done? Sir, all of a sudden, the Supreme Court decided the age bar of 55. Who has been affected by this? I do not want to name the Chief Justice of a High Court who has been affected by this decision. Sir, the Chief Justice is from Kerala, who belongs to a down-trodden section of society. He would have been the Chief Justice of the Supreme Court, if he had not been affected by this. He was denied the chance of becoming the Chief Justice of India. I raised this matter on the floor of the House earlier. The issue of this age bar has come, and he is still continuing as Chief Justice in one of the High Courts. You have done nothing. This Government has done nothing. I

charge this Government for this because had the Government not taken this course, a Dalit would have been the Chief Justice of India. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : I am not disputing or supporting the points raised by Shri Ravi. He has named the first citizen in his argument. I do not whether his argument is on the positive side or the negative side. I also do not know whether he can quote from the speeches and writings of the President. ... ...*(Interruptions)*... I do not want to go into these things. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI) : It is better to avoid this ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, if the precedent is anything to go by, I can show you the proceedings of this House. ...*(Interruptions)*... This is only the double standard. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): I am afraid, at the moment, please do not ...*(Interruptions)*... He has already made his point. Please do not waste any further time of the House on this issue. ...*(Interruptions)*... Let him continue. Let him go to the next point. Mr. Ravi, you have only three minutes left.

SHRI VAYALAR RAVI : Sir, I will abide by your rulings. Sir, I am quoting from page 3 of the President's Address. It has been said, "The approach to India's economic development may have changed in the past ten years, but the goals of equity and social justice have not. We shall re-double our efforts to ensure that the poor and the deprived have an even greater stake in economic reforms than at present." Sir, yesterday, the Minister refused to answer. Now, I would like to know about the term 'doubling'. You are doubling the kerosene price. The PDS issue price of rice and wheat has been doubled. You are doubling everything which is related to the poor. Sir, this is the document. Last year, when you came to the power, you issued 7.7 million tonnes of foodgrains. Now, what is the take-off for the PDF? The take-off is 2.59 million tonnes. The take-off is not there because the Government have increased the price. I request the Government to kindly look into this. Sir, through you, I appeal to the Government to look into this. So much of foodgrains is issued to the PDS, but the take-off is not even 30%. It shows that the poverty is increasing because you are doubling the

price. Sir, I agree that they are benefiting the rich because they throw away everything. Sir, the worth of the public sector units, in this country, is to the tune of Rs. 2 lakh crores. It is our national wealth. They are assessing these public sector units on the basis of investment which was made 100 years ago. They are not re-evaluating it. Look at the whole thing. A unit of the Modern Food Industries, in Kerala, has been sold only for Rs. 109 crores. The land value of this unit is more than Rs. 1000 crores. Sir, they are throwing away all the public sector units in the name of restructuring and in the name of privatisation which is a crime against the national wealth. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Are you criticising Dr. Manmohan Singh?

SHRI VAYALAR RAVI : I have never said about Dr. Manmohan Singh. He has introduced the process of liberalisation and privatisation in this country. He saved the nation from a financial crisis and nobody is demanding a deviation from what he had started. But your aggressive way of doing it, is not good. You are throwing away the national wealth at a cheaper price to the vested interests. This is your objective. Liberalisation does not mean privatisation. Sir, I admit the reality that the States should get more freedom. That freedom was given by Shri Narasimha Rao, by Dr. Manmohan Singh. Sir, more economic freedom, more freedom for development should be given to the States. Nobody can reverse that process. But in that process, we have to see as to how we can help the poor. They say subsidy is the biggest enemy of this country.

The concept of the NDA Government is that the subsidy is the enemy. Does Mr. Siva agree with their concept? Does the TDP agree with their concept? I know that the Tamil Nadu Government is spending Rs.1,300 crores on subsidy. I appreciate them, but this burden has shifted from Delhi.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. N. CHATURVEDI): You appreciate them, but you look towards me.

SHRI VAYALAR RAVI: I look at the more beautiful face, Sir.

My point is that the economic burden has been shifted from Delhi to Chennai, from Delhi to Hyderabad and from Delhi to Trivandrum. This is not good financial management. Subsidy is one of the major safety network for the poor. The bogus slogan of this Government is that the benefit has

percolated to the poor. You make a speech here. But you double everything. Poverty is also being doubled because the National Sample Survey says that the poverty has gone up. This is the situation today. We have to examine that.

So, Sir, only this debate can throw away the mask of this Government and reveal the real face of the NDA. That real face is insensitive to the poor. You have no sensitivity at all. This Government is very much insensitive to the cause of the poor. This Government is very much insensitive to the cause of the minorities. You are very much allergic to Dalits who could occupy the highest positions in this country. That is the sentiment that is provoking you for the constitutional review.

Thank you, Mr. Chairman.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Vice - Chairman, Sir, today is the 24th of April. Mahamahim Rashtrapatiji gave his Address to the Joint Houses on February 23. I find it disquieting that we are discussing his Address after almost two months. It does not speak well of our functioning.

In the final paragraph of his Address, on the 23rd of February, Mahamahim Rashtrapatiji has mentioned that this is a Budget Session and that a lot of work has to be done. Two months have passed, but not a word of the Budget has been discussed so far.

The President's Address of February 23 has to be discussed, has to be reviewed, has to be seen, in the context of his original Address to both Houses of Parliament on October 25, 1999. The original Address of October 25 was in the nature of a declaration of the intent of this Government, a memorandum of understanding, if you please, which was mentioned to the people's representatives. The Address that we are discussing today, the Address of February 23, is in the nature of a progress report, which the Government is presenting through the medium of the President's Address.

As far as the Government's record is concerned, though I do grant that they have been in office for less than a year, the Government have attempted many things. They have made progress on some fronts. They have made blunders on some issues. But the entire course of the legislative business which we have witnessed in the last session and this session proves the truth of an old saying in the service in which I had the privilege to serve

for forty years, and that is, "No plan survives contact with the enemey." So, finally, whatever the intentions of the Government were, the reaction from the Opposition was there, and the progress has been sporadic, accordingly.

The President's Address covers many points. I can only speak about a few of them. I take up the issue of secularism, which was emphasised right at the beginning of the Address of October 25, and slightly mentioned in the second Address of February 23. I am afraid, Sir, this Government, on the issue of secularism, has created many self-inflicted injuries, which were unnecessary, not required and which took up the time of governance, which could have been best spent on many other important issues.

I refer to issues like the decision of the Gujarat Government to lift the ban on the RSS, the controversies surrounding the filming of the movie, 'Water', at Varanasi, and the Indian Council of Historical Research. All these were avoidable issues. With a bit of maturity, balance and understanding, they could have been avoided and the work of the Parliament could not have been held up. In legal parlance, these are matters which could have been settled out of court.

The Government professes secularism, and I find no need to doubt their intentions. I am sure, they mean that they would like to be secular, but, unfortunately, ill-timed statements, and ill-timed views, which have been aired by people perceived to be either part of the Government or of organisations connected with the Government, have created an atmosphere of unease and insecurity amongst the minorities, which, again, could have been avoided if the Government had the necessary farsight, the necessary maturity and the necessary balance to ensure that members of the Government, whether at the Centre or in the States, or of various associations, which are perceived to be linked to the Government, had adhered to the Government's stated intentions of appearing to be secular. I use these words 'appearing to be' advisedly because of the background of history. By that, I refer to the sequence of events which started off with the demolition of the Babri Masjid. Because of this background, this particular Government must not only be secular, must not only be appear to be secular, but demonstrate that it is secular. These are not helped by its Members, Ministers and State Governments, who are stating that the Mandir will be built, come what may; it is not helped by members of the Governmnet and MPs providing assurance of legal aid to a person who was concerned with the killing of the Australian

missionery, Mr. Staines. It is not helped when attacks on minority Christians take place in the State of Gujarat, which is ruled by the BJP; it does not help when there are a series of attacks on Christian minorities in the State of Uttar Pradesh, which is again ruled by the BJP. As against that, let me also say that the attacks on the Australian missionery, Mr. Staines, and other Christian minorities in the State of Orissa occurred during the Congress regime. That does not really compound the offence.

Next, I would like to say a few words on the stated economic policy of this Government. As the late Chairman, Deng Xiao-peng, in China said: " It does not matter whether a cat is black or grey, as long as it catches the mice." In our previous economic policies, we had been following the socialist pattern of economy. The whole nation is changing grey. The cat is also changing colours. In the original President's Address delivered on October 25, on economic policy statement, one of the main issues the Government had emphasised was the creation of one crore jobs a year. Besides reminding the Government that this statement was made in October last year and October this year is about five or six months away, I would point out the number of jobs created is yet to be computed. I do not think it is anywhere near one crore extra jobs. But the fact of the matter is that this programme of job creation was most emphatically based on encouragement of small-scale industries, cottage industries and self-employment. But the Government's policy of widespread privatisation, widespread globalisation, of removing hitherto reserved items, putting them on the Open General List, appears to have struck a blow at the very root of the concept, which this Government had propounded of creating extra employment. It is also a matter of grave unease to many of us in the country that valuable assets of public sector enterprises are being disposed of without ascertaining their true value. Our honourable colleague, Mr. Vayalar Ravi, has mentioned about the Modern Food Industries Ltd., but there is a whole list of such public sector enterprises whose valuation has not been carried out. This morning, there was a debate on it; and questions have been put whether the assets which are being disposed of in the course of restructuring and privatisation have actually been valued at all. What price are we getting for it? This must be clarified to the House so that our minds are set at rest that we are not selling of our PSUs at whatever price we may get. For example, the disposal of SAIL.

The other aspect which the Government must bear in mind is that the stated objective of privatisation is to utilise the funds realised by the

restructuring, by the privatisation of the public sector assets, and channel these funds into the social sector. But it must be understood also that this is a one time action. When this money runs out, there will be no further money available for the continuing social sector activities, again and again, in the foreseeable future. I hope the Government is paying attention to that. It must also be understood that all economic policies have a social aspect. The Mumbai Stock Exchange is not the only indicator of the country's worth. A truer indicator of the country's well-being would be the human development index to which I do not think this Government has been paying enough attention, to link it with the effects of privatisation.

All in all, the Government must create an Indian model. The privatisation model which we are following in this country is borrowed straight from the West. India is a country of one billion people. The social effects of privatisation in a country like India are totally different from what it is in other countries, when they have been applied in Russia or in East Europe or Central Asia or in America itself. We have to evolve an Indian model of economics. It may involve privatisation of public sector units. We have to evolve our own model so that the social effects are minimised.

The President's Address refers to the development of the North-East. This point has been emphasised in both the Addresses. I have no doubt that the Government is serious about devoting time, resources and efforts to develop this neglected corner of our country. About Rs.10,200 crores has been allotted by the Government for development of industries, providing local employment in the North-East part of our country. But I am afraid, with the disturbed conditions prevailing in the North-East of our country, there is no chance for the private industry to move to the North-East. Unless industries are established in the North-East, local employment will not be created. This is a dilemma which the Government has got to overcome. What is the answer? There is an answer. If we go back to our own history, you will find it. In the First, Second and Third Five Year Plans, when the public sector was first established, one of the reasons was that these could be located in extremely backward areas of our country because these were Government enterprises, they could be told where to go. Around the PSU plants in Rourkela, Bhilai, Durgapur we can see tremendous modernity and townships have come up. The area has been developed around a nucleus of public sector enterprises. Is that possible? Would the Government consider utilising the same principle, perhaps, in a modified scale to establish public

sector industries in the far North-Eastern region of our country where the private sector will not go. There are no incentives for them. They will not go. Is it possible that the Government may like to consider setting up public sector industries, perhaps, on a modified scale, in these specific areas, so that the process of commercial development of these areas takes off?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Now, Mr. Roy Chowdhury would like to wind up.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: My last point, Sir, concerns Jammu and Kashmir. I was very happy to note that a major development, after the speech, was the offer of the Government of India to talk to the All-Party Hurriyat Conference. Of course, the All-Party Hurriyat Conference has already laid down its conditions that it shall have to involve Pakistan and the All-Party Hurriyat Conference shall be the only representative of the Kashmiri people. This is a danger which, I am sure, the Government is alive to because if any such talks take place, any third party participation, that is, the participation of Pakistan or the exclusive rights claimed by the All-Party Hurriyat Conference to represent all sections of the Kashmiri people should not be accepted.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair]

If these talks take place, then all sections of Kashmiri public, whether it is in the Valley, whether it is the Panun Kashmir, whether it is the political parties in Jammu and Ladakh, they must be taken into confidence before such talks take place. The Government must understand and the nation must be prepared for a long drawn-out war in Kashmir. Kargil, about which we keep talking, is merely a phase in this struggle, a phase in this proxy war, which started in 1988-89 and reached a high level in Kargil in 1999. It has gone back to the same level again. But hostilities are continuing. So, while we talk to Pakistan--surely, we must talk to Pakistan-- it must be understood that Pakistan is not going to give up attempting to acquire Kashmir because, to Pakistan, it is not a political or geo-political question at all. It is an emotional, psychological, question, a question of revenge for Bangladesh. We must keep all these facts in mind and certainly, we must keep our channels of communication open to Pakistan in the hope that they will see reason. But, in the meanwhile, we must be prepared to defend every inch of our territory in Kashmir.

With these words, Sir, I conclude my remarks. I thank Mahamahim Rashtrapatiji for his Address to us. Thank you very much.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा कल जारी रहेगी और अगले वक्ता श्री दुग्गल होंगे। Statement by the Minister on match-fixing.

STATEMENT BY MINISTER

Match-fixing in Cricket

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA): Sir, Government is seriously alarmed by the recent revelations regarding match-fixing in cricket, specially in the context of the recently concluded series between India and South Africa. The Delhi Police, on the basis of information in its possession, has ledged FIR No.111/2000 in this connection against Mr. Hansie Cronje and others. Keeping in view these developments, the Department of Sports summoned all the concerned agencies and officials, to get an insight into the various facts of this particular case. The case is under investigation and the full dimension of this problem will only be apparent once the detailed investigation gets completed. However, the Department is keeping a watch on developments in this case on a regular basis. This investigation will require full support of the persons and agencies concerned. The Board for Control of Cricket in India (BCCI) has assured that it will extend its complete co-operation in this regard so that the culprits could be discovered. They are also agreeable to making the Chandrachud Report public.

Other than the specific FIR registered by the Delhi Police, Government does not, at this stage, have any specific complaint against particular Indian cricketers or office- bearers of the Board for Control of Cricket in India. Allegations of a general nature are however, being reported in the media. Nevertheless, Government will in all seriousness, initiate necessary legal measures against practices of match-fixing on the basis of specific complaints that may be received, after appropriate inquiry and necessary investigation. The Government will take recourse to all legal measures to ensure that this menace is not only curbed but eliminated. It will not hesitate to order detailed investigation by any agency of the Government depending upon the gravity of the charges and allegations.